E-ISSN: 2708-4523
P-ISSN: 2708-4515
AJMC 2025; 6(2): 353-360
© 2025 AJMC
www.allcommercejournal.com
Received: 18-06-2025
Accepted: 22-07-2025

डॉ. भुवन चन्द्र मेलकानी
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड, भारत

मुकेश चन्द्र उपाध्याय
शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, एम. बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड, भारत

Corresponding Author:
डॉ. भुवन चन्द्र मेलकानी
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड, भारत

ग्रामीण कृषि साख व्यवस्था में सहकारी बैंकों के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन (पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक के विशेष सन्दर्भ में)

भुवन चन्द्र मेलकानी, मुकेश चन्द्र उपाध्याय

सारांश
भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य को संचालित करने के लिए किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई,यंत्र आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक संगठित और विश्वसनीय साख प्रणाली की आवश्यकता होती है। जिसे कृषि साख व्यवस्था कहते हैं। इस संदर्भ में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाते हैं। सहकारी बैंक किसानों को अल्प ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। जिससे उन्हें साहूकारों के चंगुल में फँसने से मुक्ति मिलती है। जिला सहकारी बैंक उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत एक प्रमुख ग्रामीण बैंकिंग संस्था है। जो पर्वतीय क्षेत्र में भी किसानों तक कृषि साख की पहुँच सुनिश्चित कर रहा है।

कूटशब्द : सहकारी, किसान, साख, समितियां, ग्रामीण बैंकिंग, सहकारी बैंक

प्रस्तावनाः
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक शक्ति कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए किसानों को समय पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है जिसे कृषि साख कहा जाता है। किसानों को यह साख बीज उर्वरक कीटनाशक कृषि यंत्र सिंचाई तथा फसल के बाद विपणन जैसे अनेक उद्देश्यों के लिए चाहिए होता है। यदि यह साख समय पर और सुलभ दर पर उपलब्ध न हो, तो किसान या तो उत्पादन में असमर्थ हो जाता है या फिर उसे निजी साहूकारों के पास ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में सहकारी बैंक ग्रामीण कृषि साख व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्थानीय स्तर पर, न्यूनतम ब्याज पर सरल प्रक्रिया के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों की पहुँच कठिन है। वहाँ सहकारी बैंक ग्रामीण विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।
भारत में सहकारी साख का इतिहास बहुत पुराना है वस्तुतः सहकारी समितियों की शुरूआत 1904 में की गई भारत में सहकारी साख संगठन का स्वरूप संघीय है सबसे नीचे प्राथमिक कृषि एंव साख समितियां है इनके ऊपर सहकारी बैकिंग युनियन एंव केन्द्रीय सहकारी बैंकों होते है राज्य सहकारी बैंक प्रत्येक राज्य में सहकारी साख संगठन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है भारत के समस्त सहकारी साख संस्थाओं पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण होता हैं।
भारत में सहकारी आन्दोलन की यह विशेषता है कि कृषि साख को असाधारण महत्व दिया गया है भारत में सहकारिता का प्रारम्भ भी प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा ही हुआ था अब भी देश की अधिकांश सहकारी समितियां यही है दस अथवा दस से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते है। इस प्रकार की समिति की स्थापना के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक विवरण भेजकर समिति का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सहकारी समितियां साधारणतया उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देती है। समिति द्वारा ऋण उधार लेने वाले की शोधन क्षमता को ध्यान में रखकर दी दिया जाता है जो सामान्यतः उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नही होता है।

सहकारी साख संगठन का स्वरूप
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
⇩
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक (नाबार्ड)

राज्य सहकारी बैंक
⇩
जिला सहकारी बैंक
⇩
प्राथमिक सहकारी साख समितियां

कृषि साख की अवधारणा

कृषि साख का तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जो किसानों को कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए प्रदान की जाती है। यह साख तीन श्रेणियों में होती है।

- अल्पकालिक ऋण रू बीज खाद सिंचाई जैसे मौसमी कार्यों हेतु।
- मध्यकालिक ऋण रू यंत्र, पशुपालन, उपकरण हेतु।
- दीर्घकालिक ऋण रू भूमि सुधार, गोदाम निर्माण, सिंचाई संरचना हेतु।

इन ऋणों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्वि कर किसान की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।

साहित्य का पुनरावलोकन

शोधकार्य से सम्बन्धित अध्ययन करने के लिए शोध साहित्य का पुनरावलोकन निम्नानुसार है–

आई. शर्मा (1985) ने राजस्थान के अल्पकालीन कृषि ऋण का विश्लेषण किया केन्द्रीय सहकारी बैंक के संदर्भ में अध्ययन से पता चला कि अल्पकालीन ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऋण नीतियों और प्रक्रियाओं को फसल ऋण प्रणाली के आधार पर होना चाहिये। यह भी देखा गया कि ऋण किश्तों में दिया जाना चाहिये और चुकाने योग्य ऋण के बीच में एक ऐसी समयावधि हो कि बुवाई और कटाई का समय किसानों को उचित मिले जिससे वह अपने ऋण को उचित तरीके और समय पर चुका सकें। साथ ही साथ बुवाई और कटाई के लिये ऋण उस समय ही मुहैया कराया जाये।

श्रीमती निर्मला चौधरी (1991) ने अपना अध्ययन केन्द्रीय सहकारी बैंक का कृषि वित्त व्यवस्थाओं में योगदान (भिण्ड जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर किया था। प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्ययन का उद्वेश्य भिण्ड जिले में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का कृषि वित्तीय व्यवस्था में योगदान का मूल्यांकन करना है। बैंक द्वारा जिले में कृषकों को प्रदत्त अल्पकालीन व मध्यकालीन कृषि ऋण का विवेचना तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण का ऋणी सदस्यों को कृ षि उत्पादन एंव उपभोग स्तर आदि पर था।

नागराज, आर सी (2010) सहकारी बैंक, उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर, किसानों के लिए ऋण के प्रावधान और गतिशील क्रेडिट के लिए बेहतर संस्थानों के रूप में पहचाने जाते हैं। सहकारी बैंक छोटे ग्रामीणों की बचत जुटाने और उसी का उपयोग कर, इसके अलावा निधियों अन्य स्रोतों से जुटाए कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न विकास क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्त पोषण में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

विपन कुमार व सोनिका धन्ना (2017) हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की वर्तमान स्थिति तथा कार्य निष्पादन क्षमता का अध्ययन करना था। अध्ययन में आँकडों के विश्लेषण हेतु अनुपात विश्लेषण का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों में पाया गया कि बैंक की अंशपूंजी में वृद्धि हुई ऋण समता अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहा है तथा ऋण जमा अनुपात बहुत अच्छा रहा है।

परोहित आर.सी और खान समरीन (2015)–अपने अध्ययन उत्तराखण्ड में कृषि साख का प्रबन्ध में इन्होने पाया कि कृषि साख सम्बन्धि सुविधाएं वर्षवार बढ रही है जिसमें छोटी और सीमान्त किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। बैक एवं सरकार ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में और अधिक व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को किसान केडिट कार्ड से कृषि ऋण और इससे सम्बन्धित अनय ऋण में बढाने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड के विकास एवं विस्तार के लिए कृषि ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है।

पटेल बनसी एम0 (2019) ने अपने अध्ययन में उन्होने पाया कि कृषि गुजरात का महत्वपूर्ण भाग है, भारतीय कृषि में भी इसका गुजरात का बड़ा योगदान है यहां कृषि भी अनेक कारकों पर निर्भर करती है यह पाया गया है कि कृषि साख में इस राज्य में निस्तर वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा किसानों को शिक्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए है तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि नीतिया लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैकों की और अधिक शाखाऐं खोलने की आवश्यकता है केवल कृषि साख प्रदान करने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा सरकार ने उचित ऋण वितरण प्रणाली बनानी होगी उसकी समय–समय पर जॉच करनी होगी। क्षेत्रवार और बैंक वार प्रभावशाली निरीक्षण की आवश्यकता है ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ–साथ लोगों के रोजगार और जीवन स्तर में वृद्धि हो।

अध्ययन की आवश्यकता

इस शोध का उद्देश्य पिथौरागढ़ जिले की कृषि साख व्यवस्था में सहकारी बैंक की वर्तमान स्थिति, योगदान, चुनौतियाँ और संभावनाओं का विश्लेषण करना है। पर्वतीय क्षेत्रों की जटिलताओं के मध्य सहकारी बैंक किस हद तक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। यह जानना महत्त्वपूर्ण है।

अध्ययन का उद्देश्य–शोधकार्य के निम्नलिखित उद्देश्य है।

- ग्रामीण साख में सहकारी बैंकों के योगदान का अध्ययन करना।
- जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ का शाखा विस्तार एवं प्रगति का अध्ययन करना।
- जिला सहकारी बैंक द्वारा पिछले 5 वर्षो में दिये गयें कृषि ऋणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- जिला सहकारी बैंक की सीमाओं का पता लगाना तथा भविष्य हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना निरूपण–शोध अध्ययन हेतु निम्नांकित परिकल्पनाऐं निरूपित की गयी है।

- H_1 पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि साख के विस्तार में जिला सहकारी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- H_2 सहकारी बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो तक वित्त पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

अध्ययन का क्षेत्र–चूंकि ग्रामीण साख वर्तमान में विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यक बैंको की शाखाओं के साथ–साथ सहकारी बैंकों के द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ का चयन इस कारण किया गया है क्योंकि उत्तराखण्ड में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों एंव भूमिहीन कास्तकारों दस्तकारों तथा निर्बल वर्ग के लोगों की साख को ही आवश्यकता नहीं होती वरन कृषि आगतों विभिन्न प्रकार की अग्रेतर एंव पृष्ठेत्तर समर्थन तथा विपणन इत्यादि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की सुविधाऐं सहकारी समितियों के द्वारा ही प्रायः की जाती है। और जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ के अन्तर्गत इस प्रकार की कई समितियों जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियॉ (पैक्स) तथा किसान सेवा समितियां कार्यरत है जिन्हें इस बैंक द्वारा पुर्नवित्त सहायता भी दी जा रही है।

अध्ययन की विधि–प्रारम्भिक चरण में ग्रामीण साख के क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक एंव द्वितीयक संमको का संकलन किया गया। प्राथमिक संमको में पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों का साक्षात्कार एंव मौखिक जानकारी प्राप्त द्वितीयक संमको का संकलन पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक लीड बैंक एंव पिथौरागढ में स्थापित अन्य सार्वजनिक एंव निजी बैकों के द्वारा प्रकाशित एंव अप्रकाशित रिपोर्टस, बैंको की वार्षिक ऋण योजनाओं के अप्रकाशित विवरणों के माध्यम से कार्य निष्पादन का गहन अध्ययन एंव विश्लेषण किया गया।

अध्ययन का महत्व–सहकारी बैंको का ग्रामीण साख में सबसे अधिक योगदान है इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ जाता है। जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ के अध्ययन से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जिला सहकारी बैंक और इसकी शाखाऐं ग्रामीण साख में अपनी सेवाऐं और सहयोग देकर पिछडे हुए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य कर रही है। यह अध्ययन जिला सहकारी बैकों के निष्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण पर आधारित है अतः इनकी भूमिका एंव ग्रामीण विकास में योगदान को भविष्य में अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होगा। अध्ययन में क्षेत्रीय एंव आंचलिक विकास के संभावना युक्त क्षेत्रों को भी रेखांकित किया गया है जिससे न केवल क्षेत्रीय विकास के नए क्षितिजों की पहचान हो सकेगी बल्कि बैंको को भी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत क्षेत्रों मे नए संभावनाओं को तलाश करने में सहायता मिल सकेगी। आशा ही नहीं वरन विश्वास भी है कि यह अध्ययन अपनी सीमाओं के बावजूद गरीबों में सबसे गरीब के भाग्योदय में सहकारी बैंकों की भूमिका को और अधिक कारगर बनाने में सफल हो सकेगा।

पिथौरागढ़ ज़िला परिचय–उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की भोगोलिक परिस्थितियाँ सीमित सिंचाई सुविधाएं और बिखरी कृषि भूमि किसानों के लिए अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। ऐसे में कृषि साख व्यवस्था का सुदृढ़ और सुलभ होना अत्यंत आवश्यक है। पिथौरागढ़ ज़िला उत्तराखंड का एक सीमावर्ती एवं पर्वतीय जिला है जहाँ लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कृषि ऋण वितरण महिला समूहों को सशक्त करने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसलिए जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ की भूमिका का गहन विश्लेषण इस अध्ययन का केंद्र बिंदु है।

तालिका–1: आधार भूत आंकड़े जनपद पिथौरागढ / चम्पावत

क्र0	विवरण	पिथौरागढ	चम्पावत
1	स्थापना	24 फरवरी 1960	15 सितम्बर 1997
2	तहसील	12	5
3	विकास खण्ड	8	4
4	जनसंख्या 2011	462289	224461
	पुरूष	227615	110916
	महिलायें	234674	113545
	ग्रामीण	402456	191727
	शहरी	59833	32734
	अनु0 जाति	106449	27372
	अनु0 जनजाति	19279	279
	कृषक	74361	34378
	कृषक मजदूर	615	520
	अन्य	49086	21267
5	भूमि कुल प्रतिवेदन क्षेत्र	410642है0	238637है0
6	ग्राम	1579	651
7	ग्राम सभायें	644	249
8	न्याय पंचायते	64	24
9	पैक्स	74	23

स्रोत–49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़

परिचय, पूँजी प्रबंध एंव संचालन ,भूमिका ,शाखा विस्तार ,जमा ऋण एंव ग्रामीण विकास–जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़

पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक की स्थापना 18 अक्टूबर सन 1962 को हुई थी। बैंक के प्रथम सभापति श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस. जिला अधिकारी नियुक्ति / नामित को जिनका कार्यकाल 18.04.1962 से 31 मई 1964 तक रहा । बैंक स्थापना दिवस से बैंकिग कार्य करने लगा था । बैंक 1965 से लगातार रूप में लाभ अर्जित कर रहा है बैंक का कार्य क्षेत्र जनपद पिथौरागढ एंव चम्पावत तक सीमित है। वर्तमान में इस सीमान्त जिला पिथौरागढ में चम्पावत जिले को मिलाकर जिला सहकारी बैंको की कुल 28 शाखाऐं एंव मुख्यालय कार्यरत है । जनपद पिथौरागढ में कुल 19 एंव जनपद चम्पावत में 09 शाखाऐं कार्यरत है तथा ग्रामीण साख में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

पूॅजी के साधन–जिला सहकारी बैंक प्रायः चार साधनों से पूॅजी प्राप्त करते है अपने अंशो की बेचकर सुरक्षित कोष से सदस्यों या गैर सदस्यों द्वारा जमा की गयी रकम से तथा अन्य साधनों से ऋण प्राप्त करके अंश पूजी के अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ जमा के रूप में अधिक रकम प्राप्त करता है वास्तव में व्यापारिक बैंक की भॉति जमाएं जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ के साधनों का महत्वपूर्ण भाग है। जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ अपनी पूॅजी में राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करता है। बैंक का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा होता है जिसके अधिकतर प्रतिनिधि प्राथमिक सहकारी साख समितियों के होते है ये समय समय पर बैठक बुलाकर इनकी नीति निर्धारित करते हैं संचालकगण अवैतनिक कार्य करते है इससे कार्यरत सभी कर्मचारी वेतन भोगी कर्मचारी होते है। और इनके कार्य आदि का नियन्त्रण बैंक का अध्यक्ष अथवा सचिव करता है। इस बैंक के सम्बन्ध में सामान्य नीतियॉ प्रदेश के सहकारी विभाग द्वारा तय की जाती है। संचालकगण केवल विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में दिशा संकेत प्रदान करता है।

भूमिका—यद्यपि जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ का कार्य प्राथमिक सहकारी साख समितियों की सहायता करना है परन्तु मुख्य नगर में स्थित होने के कारण ये बैंक प्रायः व्यापारिक बैंको की सभी कार्यों को करते है जिले के सभी सहकारी समितियों को अपनी अतिरिक्त रकम अनिवार्य रूप से इस बैंक में जमा करने पडती है इसके अतिरिक्त ये बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज का लालच देकर जनता की जमाऐं प्राप्त कर लेते है। इस प्रकार इन बैंकों के पास काफी जमाऐं हो जाती है । ये बैंक आवश्यकता पडने पर राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। ये बैंक अधिकांश ऋण तो अपने सदस्य सहकारी समितियों को देता है परन्तु गैर सदस्यों को भी ऋण देने में भी इसे कोई रूकावट नही होती । इनके ऋणों की अवधि एक से तीन वर्ष होती है कृषि ऋण प्रायः विनिमय पत्रों के आधार पर दिए जाते है। और ये बैंक इन जिलों को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पुर्न कटौती लेते है। समितियों को दिये गये ब्याज की दर 10से 14 प्रतिशत तक होती है कुछ ऋण कम ब्याज पर भी दिये जाते है जिनके लिए रिजर्व बैंक उधार देता है।

शाखा विस्तार—02.10.1962 को जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ (प्रधान कार्यालय) की स्थापना के बाद से यह बैंक जिले में अपने कार्य सुचारू ढंग से कर रहा है इसके बाद 23.03.1967 को डीडीहाट में तथा 02.09.74 को पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक की सामान्य शाखा की स्थापना की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण वित्त सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार के बैंको की ग्रामीणों को आवश्यकता रहती है। इस लिए इस बैंक की शाखाऐं पिथौरागढ और चम्पावत दोनो जिलों के सुदूर क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है। जो प्रशंसनीय है। जिला सहकारी बैंक की अपनी स्थापना के बाद से लेकर आज तक 28 शाखाऐं समूचे क्षेत्र में ग्रामीण हितो को ध्यान में रख कर अपनी सेवाऐं दे रही है। जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ के अन्तर्गत आने वाली सभी शाखाऐं अपने प्रारम्भिक कृषि समितियों अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों राजकीय कर्मचारियों तथा जमाकर्ताओं की विविध प्रकार से सेवा कर रही है। जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ लि0 की अधिकतर शाखाऐं 1970 से 1980 के बीच 8 शाखाऐं तथा 1980 से 1990 के बीच भी 8 शाखाऐं खोली गयी 1991 में केवल एक शाखा खुली जो खेतीखान में है। 2000 के बाद 2003 में एक तथा 2004 में तीन शाखाऐं खोली गयी है । 2011 में 1 शाखा कोटमन्या और 2013 में 2 शाखाऐं जौरासी और किमतोली में खोली गयी तथा 2016 में विकास भवन पिथौरागढ में 1 नई शाखा का उदघाटन किया गया। 2019 में एक महिला शाखा पिथौरागढ़ में तथा 2021 में एक महिला शाखा लोहाघाट में खोली गयी।

तालिका–2: बैक की प्रगति एक झलक में (धनराशि लाख में)

क्र0	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1	अंशपूजी	839.78	905.19	1071.54	1168.27	1252.98
2	निधियां	8090.64	8904.54	9334.39	10873.78	6359.31
3	निजी पूंजी	8930.42	9809.73	10405.93	12042.05	77880.88
4	निक्षेप	77975.01	82476.65	89082.55	93566.73	95310.88
5	वाहय ऋण (शीर्ष बैंक व अन्य बैंको से)	17836.16	14674.53	16938.32	13437.48	23137.24
6	कार्यशील पूजी	107238.03	111815.56	120999.74	122912.91	135906.76
7	विनियोजन	62248.52	56205.42	57405.81	54177.85	61229.35
8	ऋण व अग्रिम	36545.76	46287.34	55465.72	58740.32	65003.36
9	शुद्ध लाभ	312.88	453.03	536.88	418.31	268.59
10	प्रबन्धकीय व्यय का प्रतिशत (कार्यशील पूंजी से)	1.66	1.72	1.98	2.25	2.31
11	प्रबन्धकीय व्यय का प्रतिशत (सकल आय से)	24.47	22.17	26.75	30.88	32.84
12	कुल आय	7271.47	8666.85	8947.05	8953.31	9580.07
13	कुल व्यय	6958.59	6803.82	7313.18	7229.57	7698.22
14	वसूली प्रतिशत	82.50	59.30	61.01	57.60	59.67
15	आडिट वर्गीकरण 'क'	क	क	क	क	ख+

स्रोत–49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़

बैंक द्वारा निक्षेप प्राप्ति हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही है–

- बचत खाता में दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर ब्याज देय।
- चालू खाता एवं आवर्ती खाता
- सावधि जमा खाता–तिमाही, छमाही एवं वार्षिक आधार पर ब्याज देय।
- सावधि पुर्नविनियोजित योजना तिमाही आधार पर चक्रवर्ती ब्याज देय।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खाता खोलने की सुविधा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना सुविधा लागू।
- शाखा पिथौरागढ़, चम्पावत एवं टनकपुर में लाकर सुविधा।
- बैंक की समस्त शाखाओं में RTGS/NEFT/ATM की सुविधा।
- E&Commerce- Pos/IMPS
- बैंक की ऋण योजनायें
- दोनों जनपद के समिति सदस्यों को दूधारु पशु क्रय, बकरी पालन, भेड़ पालन, खच्चर पालन इत्यादि हेतु मध्यकालीन ऋण वितरण कार्य।
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत० प्रतिशत ब्याज दर पर लघु/सीमान्त बीपीएल परिक्षा के सदस्यों को रु. 3 लाख तक ऋण सुविधा।
- जड़ी–बूटी कृषिकरण हेतु ऋण योजना।
- पैक्सों के माध्यम से व सीधे बैंक के माध्यम से रिवाल्विंग फण्ड व सावधि ऋण सुविधा विशेषकर महिला समूहों को प्राथमिकता।
- वेतन भोगी समितियों को ऋण वितरण।
- व्यवसायियों को दृष्टिबन्धक ऋण सीमा सुविधा।
- निजी कार, टैक्सी जीप, बस, ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर हेतु ऋण सुविधा।
- सेवारत कर्मचारियों को मु० 10 लाख तक उपभोक्ता टिकाउ वस्तु क्रय हेतु ऋण सुविधा।
- वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा।
- भवन निमार्ण हेतु कर्मचारियों, व्यवसायियों को ऋण सुविधा।

- उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण सुविधा।
- वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके वेतन के सापेक्ष 3500000 तक ऋण सीमा सुविधा।
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण सुविधा।
- बैंक के सावधि/आवर्ती निक्षेप के सापेक्ष ऋण सुविधाएँ

तालिका–3: जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ द्वारा वितरित कृषि ऋण (₹लाख)

वित्तीय वर्ष	जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़		
	अल्पकालीन कृषि ऋण	मध्यकालीन कृषि ऋण	कुल कृषि ऋण
2018–19	9549.45	1207.75	10757.2
2019–20	12448.58	2200.39	14648.97
2020–21	13227.97	2101.69	15329.66
2021–22	14100.73	2195.61	16296.34
2022–23	15641.03	2545.54	18186.57
योग	64967.76	10250.98	75218.74.

स्रोत–49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ

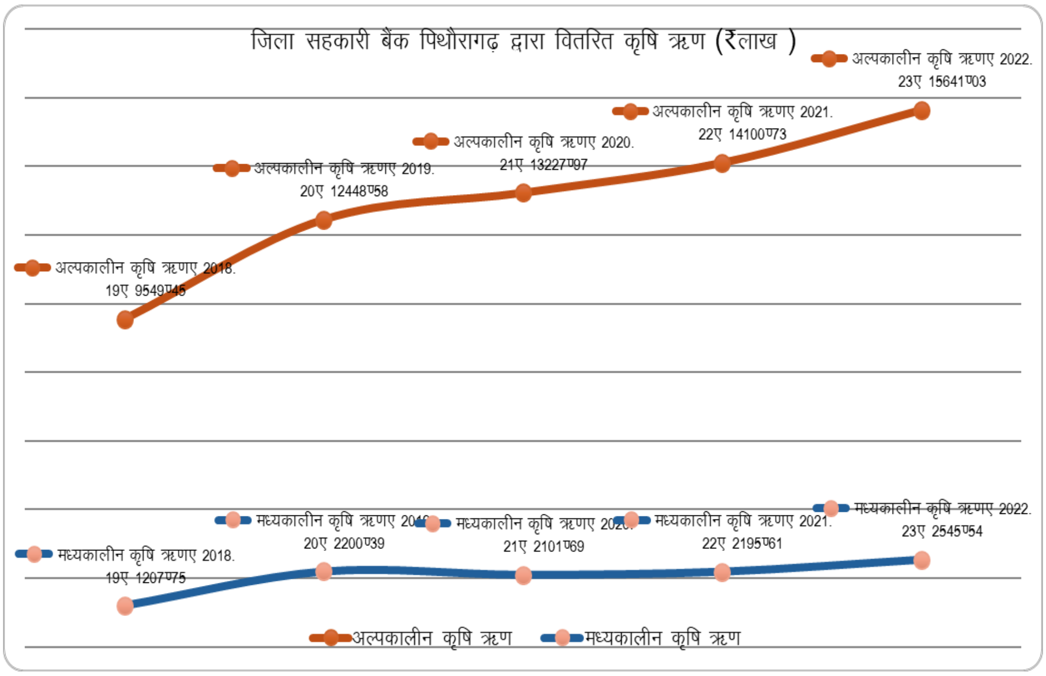

पिथौरागढ जला सहकारी बैंक लि० द्वारा समितियों को वितरित कृषि ऋणों का विश्लेषण करे तो यह ज्ञात होता है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹9549.45 लाख से बढ़कर वर्ष 2022–.23 में ₹15641.03 लाख ऋण वितरित किया गया है। सम्पूर्ण शोधकाल में बैंक द्वारा वितरित अल्पकालीन कृषि ऋणों की मात्रा में वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 में क्रमशः 34.49%, 30.36%, 5.89%, 6.19% तथा 10.92% की वृद्धि हुई है, ऋण वितरण में सबसे अधिक कमी वर्ष 2020–21 में हुई है। पिछले 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋणों के वितरण में सामान्य गति से वृद्धि हुई है। बैक द्वारा सदस्य समितियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1207.75 लाख मध्यकालीन कृषि ऋण के सापेक्ष वर्ष 2022–23 में ₹2545.54 लाख ऋण वितरित किया गया है। मध्यकालीन कृषि ऋण में वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक 23.28% की कमी हुई जबकि अगले वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक 82.19% वृद्धि हुई है। औसत रूप में जिला सहकारी बैंक द्वारा पिछले 5 वर्षो में कुल ₹64967.76 लाख अल्पकालीन कृषि ऋण तथा ₹10250 लाख मध्यकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण शोध अवधि में अल्पकालीन कृ षि ऋणों की मात्रा में मध्यकालीन कृषि ऋणों की अपेक्षा अधिक स्थिरता एवं सजातीयता रही है। शोध अवधि में बैंक द्वारा वितरित कुल कृषि ऋणों का योग ₹75218.74 लाख रहा है।

सहकारी बैकों की समस्याऐं–योजनाकाल में सहकारी बैंको द्वारा दिये गये ऋणों की संख्या में जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उसे असन्तोष जनक नहीं कहा जा सकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि सहकारी बैंक अनेक दोषों व समस्याओं के कारण केवल सीमित रूप में सफल रहा है। इसके मुख्य कारण निम्न है।

- सहकारिता का आधार स्वावलम्बन है। सहकारिता प्रारम्भ से ही सरकार पर निर्भर रही है । सहकारी बैंको के साधन उस तेजी से नही बढ पाते जिस तेजी से उनके ऋणों की मॉग बढती है। देश की आवश्यकता को देखते हुए सहकारी बैको की संख्या बहुत कम है। इसलिए ये बैंक ग्रामीण साख की समस्या को आशिक रूप से ही हल कर पाये है।
- हकारी बैंकों के पास कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारियों का नितान्त अभाव है इन बैंको में कार्यरत कर्मचारियों को न तो बैकिंग सिद्धान्तों का ज्ञान है और न ही सहकारिता के सिद्धान्तों को इसलिए बैकों का प्रबन्ध कुशलता से नही हो रहा है।
- दिये गये ऋणों की वसूली समय पर न होने पर सहकारी बैंको की बकाया राशि निरन्तर बढती जा रही है ।
- सहकारी बैकिंग व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि वह स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध बचतों को इकट्ठा कर सके तथा उसकी उच्च ऋण संस्थाओं पर निर्भरता कम से

कम हो परन्तु बहुत सी प्राथमिक सहकारी समितियॉ अभी भी जिला सहकारी बैंक पर निर्भर है और ग्रामीण बचतों को इकट्ठा करने में असफल रही है। बाहरी स्थानों पर निर्भरता के कारण समितियों के सदस्य उनके प्रयोग के प्रति अधिक सर्तक नहीं है। इसके अलावा इस निर्भरता के कारण प्राथमिक सहकारी समितियों के काम काज में बाहरी संस्थाओं का हस्तक्षेप बना हुआ है।

- अधिकतर व्यक्ति सहकारी बैंको में अपना खाता नहीं खोलना चाहते क्योंकि ये बैंक व्यापारिक बैंको की तुलना में कम सुविधाऐं देते है । अतः जहॉ व्यापारिक बैंको की शाखाऐं होती है वहॉ सामान्य जनता इन बैंकों से कोई लेन देन नही करती साथ ही सहकारी बैंकों में अनियतिताऐं तथा घूसखोरी की प्रवृत्ति फैली हुयी है जिससे किसानों को ऋण मिलने में बहुत असुविधा का सामना करना पडता है । ऋण मिलने में अत्यन्त विलम्ब होता है।
- साख समितियॉ सहकारी प्रयत्नों से स्थापित की जाती है अतः लोग यह मानते है कि यह समितियॉ सरकारी है और अनका संचालन सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये जनता इन समितियों या बैंको की सफलता के लिए विशेष प्रयत्न नही करती है।
- राजनीतिज्ञों तथा अफसरों की नीतियों के कारण सहकारी संस्थाओं में गलत कामों के लिए गलत व्यक्तियों को ऋण दिये जाते है। सहकारी संस्थाओं की ऋण नीति का एक दोष यह भी है कि उन्होने मात्र साख की व्यवस्था की तथा दूसरे पहलुओं जैसे उचित विपणन व्यवस्था उत्पादन आदि पर ध्यान नही दिया अर्थात किसानों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नही की जा सकी ।
- सहकारी बैंको की स्थापना भारतीय कृषि के उत्थान के लिए की गयी है । पिछले 70–80 वर्षो तक इस क्षेत्र का अनुभव करने के पश्चात भी भारतीय सहकारी बैंक कृषि की केवल 40 प्रतिशत के लगभग आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हो सका है। सहकारिता में जनता का विश्वास नहीं है। सहकारी संस्थाओं में लोगों की आस्था नही है।

निष्कर्ष एंव सुझाव

निष्कर्ष

- जिला सहकारी बैंक अब पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत हो चुका है तथा अन्य बैंकों की भांति अपने ग्राहकों को बैंकिग सेवा प्रदान कर रहा है
- वित्तीय वर्ष 2018–2019 की समाप्ति पर बैंक की निजी पूजी जहॉ मू0 8930.42 लाख थी 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर मू0 7880.88 लाख रूपया हो गई ।
- बैंक की अंश पूजी 31 मार्च 2019 को जहां मु0 839.78 लाख थी वह 31 मार्च 2023 को मु0 1252.98 लाख रूपया हो गई।
- 31 मार्च 2019 को जहां निक्षेप मु0 77975.01 लाख थे वह मार्च 2023 में मु0 95310.88 लाख पहुच गई ।
- बैंक की कार्यशील पूजी जहॉ मार्च 2019 को मू0 107238.03 लाख थी वह बढकर 31 मार्च 2023 को मू0 135906.76 लाख पहुच गई।
- वर्ष 2018–19 में जहॉ बैंक द्वारा कुल मू0 43475.00 लाख ऋण वितरण कार्य किया गया वही वर्ष 2022–23 की मू0 29507.38 लाख रहा।
- 31 मार्च 2019 को बैंक का कुल लगा ऋण मु. 36545.76 लाख था वह 31 मार्च 2023 को मु0 65003.36 लाख हो गया।
- 30 जून 2023 को वसूली 64.87 प्रतिशत रही जो सन्तोषजनक स्थिति कही जा सकती है उक्त ऑकडे इस बात के साक्ष्य है कि बैंक निरन्तर रूप में प्रगति कर रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में जहॉ कुल सकल लाभ मु0 999.88 लाख एंव शुद्ध मु0 312.88लाख था। वही वर्ष 2022–23 में कुल सकल लाभ मु0 1881.85 लाख एंव शुद्ध लाभ मु0 268. 59 लाख रहा।
- जनपद पिथौरागढ एंव चम्पावत की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात बैंक द्वारा अपने सरप्लस फण्ड मु0 61229.35 लाख विभिन्न बैंको में विनियोजित किया गया था।
- बैंक द्वारा अपने सदस्यों पैक्सों को और अधिक सुदृण बनाने के लिए कृषि एंव कृषियेतर ऋणों वितरण में बल दिया गया जिसके फल स्वरूप वर्ष 2018–19 में कृषि ऋण वितरण मू0 11275.04 लाख के सापेक्ष वर्ष 2022–23 में मु0 18250.58 रहा, इसी प्रकार अन्य ऋणों के वितरण कार्य में निरन्तर वृद्धि रही।
- जनपद पिथौरागढ एंव चम्पावत के कृषकों कास्तकारों की कृषि एंव अकृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पैक्स उत्तरदायी है। कृषि ऋण वितरण में यह बैंक दोनों जनपदों में अग्रणी है।
- पैक्स के ऐसे ऋणों सदस्यों को जो बकायेदार चल रहे है उन्हें वसूली का महत्व की जानकारी देकर ऋण अदायगी हेतु प्रोत्साहित करना है।
- बैंक अपनी लाभार्जन शक्ति बढाने के लिए तथा बैकिग प्रतिस्पर्धा में खडा रहने के लिए विविधिकरण के अन्तर्गत व्यवसायिक ऋण सीमा, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण टिकाऊ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रय हेतु ऋण भवन ऋण वीर चन्द्र सिह गढवाली योजनान्तर्गत ऋण ,दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना वाहन ऋण समूहों के माध्यम से ऋण ,संयुक्त देयता समूह ऋण व्यवसाय कर रहा है।
- चालू वर्ष में बैंक से पेंन्शन आहरित करने वाले पेन्शन धारकों को ऋण योजना सुचारू पूर्वक जारी हैं तथा डेयरी उधमिता विकास के अर्न्तगत दो चार व दस यूनिट को ऋण वितरण करने वाला राज्य का पहला बैंक है।
- बैंक की कुछ शाखाओं में ए0टी0एम0 कार्य करने लगा है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 सें डिजीटल साक्षरता हेतु कार्यक्रम किया गया जिससे लोगों को तकनीकी प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और उन्हें डिजिटल भुगतान सम्बन्धि सभी जानकारियॉ दी गई जैस ए0टी0एम0 का प्रयोग नकदी आहरण हेतु ई–काम में भुगतान करने तथा ए0टी0एम0 लोड द्वारा करेन्सी को बढावा देना है।

सुझाव–सभी समस्याओं का समाधान किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ सीमा तक इन समस्याओं का समाधान कर सहकारी बैंक ग्राम्य क्षेत्रों के विकास में अपनी और अधिक भूमिका प्रदान कर सकती है।

जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ अपनी 28 शाखाओ के साथ पिथौरागढ तथा चम्पावत सभी क्षेत्रों जहॉ जहॉ इसकी शाखाऐं हैं पर्याप्त प्रगति कर रहा है महिला शाखा लोहाघाट को छोड कर लगभग सभी शाखाऐं लाभ पर चल रही है। ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधाऐं देकर यह बैंक ग्रामीण जनता में अपना विश्वास बढाने में सफल रहा है।

सहकारी बैंको के विकास के कुछ सुझाओं पर ध्यान दिया जाए तो सहकारी बैंक जो सहकारी समितियों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण आंचलों में कृषकों कारीगरों व अन्य व्यक्तियों को ऋण तथा विभिन्न आर्थिक योजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आशतित प्रगति कर सकता है।

- जिला सहकारी बैंक लि0 पिथौरागढ जनपद पिथौरागढ एंव चम्पावत के आर्थिक विकास में इस बैंक के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है । भविष्य में भी यह बैंक निर्बल वर्ग, कृषकों एंव मजदूरों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करते हुए महम्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आशा है कि बैंक,केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार की किसान कल्याण योजनाओं में अधिकाधिक भागीदारी सुनिशिचित करेगा। राज्य एंव केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विकास संबधी नीतियों यथा वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ,डिजीटलाइजेशन आदि में अग्रणी भूमिका निभायेगा।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से कृषकों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ कर आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम बनाने हेतु गंभीर प्रयास किये जाने है। जिनके क्रियान्वयन में समग्र सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
- जमा राशि बैक की रीढ की हडडी है यद्यपि सहकारी बैंक लगातार रूप से निक्षेपों में वृद्धि कर रहा है फिर भी बैक जमा योजनाओं का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयार प्रसार कर निक्षेप स्थिति को और अधिक सुदृण करना चाहिए।
- 31 मार्च 2023 को ऋण जमा अनुपात 68.20 प्रतिशत था अधिक लाभदायकता के लिए इसे और अधिक मात्रा में बढाया जाना चाहिए।
- पलायन रोकने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका शासन स्तर पर नीति निर्धारित की जाए।
- फैक्स सचिवों को बैंक में समायोजित किया जाए तथा पैक्स ओवर ड्राफ्ट तथा देय ब्याज की प्राप्ति हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाए।
- सहकारी बैकों द्वारा प्रदत्त ऋण यथा भवन,वाहन,टर्मऋण की सीमाएं व्यावसायिक बैंक के अनुरूप की जाए तथा शाखा स्तर से अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जाए।
- जनपद से संचित निक्षेपों का उपयोग यह है कि कृषि ऋणों को वितरित किया जा रहा है। परन्तु सदस्य समिति के बीच वसूली की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है अतः समिति प्रतिनिधियों को वसूली में मुख्य ध्यान देना चाहिए ।
- छोटे किसानों को अधिक सहायता दी जाए जबकी बडे किसानों को उत्पादन बढाने और विकास करने के लिए इन समितियों में जमा के रूप में अधिकाधिक साधन प्राप्त किये जाये।
- ऐसी सक्षम समितियों व संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो न केवल अधिकाधिक मात्रा में साख व अन्य सुविधाऐं दे सकें वरन जमाऐं भी प्राप्त कर सकें।
- कमजोर वर्गों के लिए उपयोग सम्बन्धी ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ऋण देने में भौतिक जमानत के बजाय कृषि की उत्पादन क्षमता पर ध्यान देना चाहिए।
- सरकार और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहकारी बैंको को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए , मौसमी कृषि कार्यो की वित्तीय व्यवस्था करने हेतु कमजोर बैंको को अल्पकालीन साख में वृद्धि करनी चाहिए।
- सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर उत्तम,बीज खाद औजार तथा कीटनाशक औषधियां आदि प्रदान करके कृषकों को आधुनिक ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सहकारी साख समितियों द्वारा दिये गये ऋणों पर 12 से 15 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है जो वास्तव में अधिक है। इससे गरीब किसानों पर भारी बोझ पडता है अतः इसे कुछ कम किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक रकम बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इस धन का प्रयोग उनके हितों में किया जा सके।
- सहकारी बैंको में अनियमिताऐं तथा घूसखोरी फैली है जो नही होनी चाहिए ताकि किसानो व अन्य जरूरतमंद लोगों को ऋण मिलने में असुविधाऐं व विलम्ब न हो।
- अभी जनपद में कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां सहकारी बैंक की शाखाऐं नहीं है। गरीब ग्रामीण किसान सहकारी बैंक की सुविधा नहीं ले पा रहे है। अतः इन स्थानों पर नयी शाखाऐं खोली जानी चाहिए।
- सहकारी बैंको को कृषि ऋण के साथ–साथ आर्थिक योजनाओं व्यावसायिक आवश्यकाताओं वाहन ऋण तथा घरेलू आवश्यकओं के लिए भी अधिक ऋण देना चाहिए जो अन्य वाणिज्य बैंको के साथ प्रतियोगिता करने के लिए उचित होगा।
- पैक्स की सुदृढता पर विशेष प्रयास किये जाने,पैक्स के माध्यम से अधिककाधिक ऋण वितरण एंव वसूली हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है, पैक्स की मजबूती से बैंक भी स्वतः मजबूत होंगे तथा पैक्स व बैंक को व्यवसाय बढाने हेतु ऋण वितरण के नये क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा।

अतः संक्षेप में कह सकते है कि जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ का कार्यक्षेत्र जनपद पिथौरागढ एवम सुदूर चम्पावत के अन्तर्गत विस्तारित हैं। बैंक द्वारा दस्तकारों स्वयं सहायता समूहों को हमेशा अपनी योजनाओं का तत्परता से लाभ प्रदान किया है। बैंक द्वारा स्वरोजगार हेतु वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजनान्तर्गत पयर्टन ऋण दस्तकारों हेतु स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्वर्ग जयन्ती स्वरोगार योजनान्तर्गत को सर्वमौम स्वरोजगार योजनान्तर्गत सांग सब्जी जडी बूटी उत्पाद हेतु ऋण उपलब्ध कराने ही गैर कृषक मद में वेतन भोगियों को उनकी सहकारी समिति के माध्यम से तीन से पांच वर्षीय ऋण भवन निर्माण हेतु ऋण जिनका वेतन बैंक में आता है ऐसे प्राथमिक/बेसिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन के विरूद्ध कैश व्यापारियों पेशेवर लोगों हेतु भी भवन निर्माण वाहन कैश क्रेडिट लिमिट तथा उच्च शिक्षा हेतु ऋण इत्यादि प्रदान किये जा रहे है। प्रदेश की चीनी मिलों को कार्यशील पूजी व सावधी ऋण भी प्रदान किया जा रहा है । इस प्रकार बैंक ने जनपद पिथौरागढ एंव चम्पावत के अन्तर्गत कृषकों बेरोजगारों वेतन भोगियों व्यापारियों के साथ–साथ सर्वहार वर्ग की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु उल्लेखनीय कार्य करते हुये अपनी पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की है।

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित किसानों के लिए एक प्रभावी ऋणदाता संस्था के रूप में उभरा है। यह बैंक न केवल कृषि कार्यों हेतु ऋण प्रदान करता है बल्कि महिला सशक्तिकरण वित्तीय समावेशन और बचत प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है।हालाँकि प्राकृतिक बाधाओं और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसकी गति कुछ क्षेत्रों में सीमित रही है लेकिन उचित सुधार और सरकारी सहयोग से इसकी पहुँच और प्रभाव को और अधिक विस्तृत किया जा सकता है।सहकारी बैंक ग्रामीण कृषि साख के मजबूत स्तंभ हैं और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक इस दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि साख के विस्तार में जिला सहकारी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सहकारी बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो तक वित्त पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा एवं पूरी–भारतीय अर्थव्यवस्था (2015) हिमालया पब्लिशिंग हाउस
2. गौड़ एवं यादव–बैंक ऋण वसूली प्रबन्ध विविध आयाम, हिमालय पब्लिशिंग हाउस मुम्बई (1995)

3. योजना–नई दिल्ली, मासिक (विभिन्न अंक)
4. कुरुक्षेत्र–नई दिल्ली, मासिक (विभिन्न अंक)
5. जर्नल
6. शोध प्रबन्ध
7. www.shodhganga.inflibnet.ac.in
8. www.slbcuttarakhand.org.in
9. NAFSCOB Annual Reports 2018–2024
10. उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की वेबसाइट
11. पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2018–2023
12. वार्षिक ऋण योजना लीड बैंक पिथौरागढ
13. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
14. नबार्ड रिपोर्ट्स
15. साक्षात्कार और फील्ड डेटा संग्रह (स्थानिय लाभार्थियों से)